

खण्ड 6  
भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था

---

## खण्ड 6 भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था

---

### परिचय

भारत में राजनीतिक दल सबसे प्रभावशाली माध्यम है विधायिका एवं कार्यपालिका की प्रक्रिया में भाग लेने का। जैसा कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ पर जनता का प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना मुश्किल है। यह कार्य सिर्फ राजनीतिक दलों द्वारा ही पूरा किया जाता है। हालांकि कुछ लोग राजनीतिक दलों का हिस्सा नहीं होते वे भी स्वतंत्र रूप से लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में कई प्रकार के राजनीतिक दल हैं। उनकी कुछ विशेषताओं के आधार पर उन्हें दलीय व्यवस्था में रखा जा सकता है। इस खंड में केवल एक ही इकाई है। इकाई संख्या 15, जो कि दल एवं दलीय व्यवस्था के बारे में है। यह दलों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करती है तथा भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था कायम है इसकी भी चर्चा करती है।



---

## इकाई 15 दल एवं दलीय व्यवस्था\*

---

संरचना

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 राजनीतिक दलों का वर्गीकरण

15.3 राज्यों में दलीय व्यवस्था

15.3.1 काँग्रेस वर्चस्व का युग

15.3.2 काँग्रेस पार्टी का पतन : 1967—1989

15.4 राज्य दलीय व्यवस्था में बिखराव : 1989 से

15.5 सारांश

15.6 संदर्भ सूची

15.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

---

### 15.0 उद्देश्य

---

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप यह समझ सकेंगे :-

- दलीय व्यवस्था की परिभाषा एवं क्षेत्रीय तथा राज्य पार्टियाँ,
- विभिन्न काल में प्रभावी दलीय व्यवस्था को जानना,
- काँग्रेस के प्रभावी काल एवं उसके कमजोर होने के कारणों का पता लगाना।

---

### 15.1 प्रस्तावना

---

किसी भी लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था बातचीत एवं विभिन्न दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का तरीका है। भारत में इसी व्यवस्था ने बहु-दलीय प्रणाली को जगह दी है। इस प्रकार की व्यवस्था अभी हाल ही के दशकों में ज्यादा देखने को मिली है बजाय पहले के समय में। पहले जो व्यवस्था कायम थी। वो काँग्रेस पार्टी के वर्चस्व का समय था। इस चरित्र को सही तरीके से रजनी कोठारी ने समझाया है। उन्होंने काँग्रेस की व्यवस्था को वर्चस्व वाली व्यवस्था माना है। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस बहुत प्रभावी एवं सशक्त राजनीतिक पार्टी थी, इसने विधान सभा एवं संसद में अपनी स्थिति मजबूत कायम की एवं इसका सांगठनिक ढाँचा भी बहुत मजबूत था। कोठारी ने इस व्यवस्था को “काँग्रेस व्यवस्था” कहा था, जबकि जोन्स ने “काँग्रेस प्रभुत्व व्यवस्था” माना था। हाल ही के वर्षों में दलीय व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ है। ये बदलाव 1967 से शुरू हुए लेकिन इनमें ज्यादा परिवर्तन 1980 से 1990 के बीच ज्यादा हुआ। इस दौरान एक दलीय व्यवस्था से बहुदलीय व्यवस्था का आगमन हुआ। इसे हम संघीय दल व्यवस्था या गठबंधन दलीय व्यवस्था भी मान सकते हैं। 2014 से भारत में भारतीय जनता पार्टी एक सबसे अधिक वर्चस्व वाले दल के रूप में उभरी है। हम इस इकाई में विशेष रूप से राज्य स्तर पर विकसित दलीय व्यवस्था पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। लेकिन ऐसा करने से पूर्व हम संक्षिप्त में क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय दलों के बारे में जानकारी लेंगे क्योंकि ये दल हाल ही के वर्षों में बड़ी तेजी से उभरकर सामने आये हैं तथा ये भारतीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

---

\*प्रो. अरुण कांति जाना, राज. वि. विभाग, नार्थ बंगाल, यूनिवर्सिटी, दार्जिलिंग

## 15.2 राजनीतिक दलों का वर्गीकरण

भारत में, राजनीतिक दलों को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, शोधकर्ताओं शैक्षिक द्वारा तथा दूसरा भारत के चुनाव आयोग द्वारा। पहला, राजनीतिक दलों को उनके समर्थन, नीतियों एवं विचारधारा के आधार पर वर्गीकृत करता है जबकि चुनाव आयोग इन दलों को विधान सभा या लोक सभा के चुनावों में प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर वर्गीकृत करता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को तीन भागों में वर्गीकृत करता है। राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल तथा क्षेत्रीय पंजीकृत दल है। इस परिभाषा में राज्य पार्टी वह कहलायेगी जिसने किसी राज्य में पिछले पाँच वर्षों तक राजनीतिक गतिविधि की हो और उसने आम चुनावों में चार प्रतिशत सीटें जीती हो तथा तीन प्रतिशत राज्यों के चुनाव सीटें जीती हो। इसके साथ उसे कुल मतदान का छः प्रतिशत वोट मिला हो। लोकप्रिय चर्चा में चुनाव आयोग द्वारा घोषित राज्य की पार्टियाँ मुख्यतौर पर क्षेत्रीय पार्टियाँ होती है। ओलीवर हीथ एवं योगेन्द्र यादव ने उन पार्टियों को क्षेत्रीय पार्टियाँ माना है जिनका सामाजिक आधार एक या दो राज्यों तक ही सीमित हो।

यह परिभाषा किसी राजनीतिक दल के सामाजिक आधार एवं इसके कार्य क्षेत्र को इंगित करती है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल तभी मान्य होता है जब उसे चार राज्यों में पहचान मिली हो। पंजीकृत राजनीतिक दल वह होता है जो ना तो राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित हो और ना ही राज्य पार्टी से बल्कि उसे चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत किया गया हो। ऐसी पार्टियाँ गैर मान्यता प्राप्त दल भी मानी जाती है। चुनाव आयोग द्वारा दी गयी परिभाषा किसी क्षेत्रीय दल के लिए संतुष्ट नहीं है। क्योंकि यह परिभाषा किसी दल के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखकर दी गयी है, जिसने शिक्षाविदों ने सही परिभाषा मानने से इन्कार कर दिया। ये उन राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय मानते हैं जिनकी कार्यवाही एवं आधार किसी विशेष राज्य तक ही सीमित हो तथा उनकी जड़ क्षेत्रीय इच्छाओं एवं समस्याओं में ही हो। किसी क्षेत्रीय दल का आधार किसी विशेष राज्य तक ही सीमित होता है क्योंकि ये दल अपनी पहचान उस राज्य की संस्कृति भाषा, धर्म, इत्यादि तक बनाये रखते हैं। ये क्षेत्रीय पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। ये क्षेत्रीय दल 'क्षेत्र' एवं भाषा को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हैं चुनावी लाभ के लिये किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए तीन विशेष मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, किसी क्षेत्रीय दल को अपना आधार एवं कार्य किसी एक राज्य तक ही सीमित रखना चाहिए। दूसरा, इस प्रकार के दलों को क्षेत्र विशेष की संस्कृति, धर्म, एवं पहचान की रक्षा करनी होगी, तथा तीसरा, अपनी प्रकृति के अनुसार क्षेत्रीय दलों का संबंध मुख्य रूप से स्थानीय या राज्य स्तरीय शिकायतों से संबंधित होना चाहिये।

## 15.3 भारतीय राज्यों में दलीय व्यवस्था

भारत में राज्य दलीय व्यवस्था का विकास राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था के साथ-साथ ही हुआ है। राष्ट्रीय दलों एवं राज्य स्तरीय दलों के बीच गहरा संबंध होने के कारण राज्य स्तरीय दलों का विकास बड़ी तेजी से हुआ है। जैसा कि हमें ज्ञात है भारत में विभिन्न राज्य है। राष्ट्रीय दलों में परिवर्तन का असर राज्यों में भी पड़ा है और इसके एवज में राज्यों में दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रभाव राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था पर भी पड़ा है। दूसरी घटना हाल ही के वर्षों में ज्यादा देखने को मिली है, क्योंकि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय एवं राज्य दलों में वृद्धि हुई है।

### 15.3.1 काँग्रेस वर्चस्व का युग

1967 से पूर्व का काल भारत में काँग्रेस के प्रभुत्व का वर्चस्व का काल माना जाता है। इसे हमें 'काँग्रेस व्यवस्था' या 'काँग्रेस प्रभुत्व व्यवस्था' भी कह सकते हैं। 1967 तक या चौथे आम चुनाव तक ज्यादातर राज्यों में तथा राष्ट्रीय स्तर पर काँग्रेस का ही वर्चस्व था। लगभग सभी राज्यों में काँग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था। लेकिन सभी राज्यों के काँग्रेस का प्रभुत्व एक जैसा नहीं था। उदाहरण के तौर पर काँग्रेस पार्टी को पूर्व देशी रियासतों में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला जो 1947 के बाद भारतीय संघ में शामिल हुए थे जबकि अन्य राज्यों में उसका दबदबा कायम था। काँग्रेस की लगभग सभी राज्यों में सरकार थी सिवाय जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर जहाँ नेशनल काँग्रेस का दबदबा था। इसके अलावा केरल भी एक उदाहरण है जहाँ 1957 के आम चुनाव के बाद राज्य में सी.पी.आई. की सरकार बनी थी, जिसे बाद में गैर कानूनी तरीके से 1959 में केन्द्र सरकार ने भंग कर दिया था। कुछ आँकड़ें हमें इसमें और मदद करेंगे। 1952, 1957 और 1962 के चुनावों में काँग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसे लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभा में बहुमत मिला था। हालांकि कि इसे 48 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन इसने आवश्यक बहुमत हासिल किया था। 364 सीटें 1952, 371 सीटें 1957 एवं 361 सीटें 1962 के चुनावों में काँग्रेस पार्टी को मिली थी। राज्यों में लगभग यही स्थिति थी जहां कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में बहुमत प्राप्त किया था। इसने 1952 में 42.2 प्रतिशत वोट 68.4 प्रतिशत सीटें प्राप्त की थी, 1957 में 44.97 प्रतिशत वोट एवं 64.9 प्रतिशत सीटें जबकि 1962 में 43.65 प्रतिशत वोट एवं 61.3 प्रतिशत सीटें प्राप्त हुई थी। चुनावी आँकड़ें यह बताते हैं काँग्रेस का प्रदर्शन लोक सभा चुनावों की तुलना में राज्यों में कमजोर था। इसका कारण था राज्यों में क्षेत्रीय दलों एवं संगठनों का विरोध का सामना। विधान सभा चुनावों में काँग्रेस को लोक सभा की तुलना में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हमें इसका आकलन निम्न आँकड़ों के माध्यम से लगाना होगा।

1952 एवं 1962 उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों में काँग्रेस पार्टी को 47.9 एवं 36.3 प्रतिशत मत प्राप्त हुए एवं 430 में से 390 एवं 249 सीटें मिली थी। बिहार में, उसी दौरान, 41.4 से 42.1 प्रतिशत के बीच मत एवं 72.2 से 58.1 प्रतिशत सीटें मिली। पश्चिम बंगाल में 38.9 से 47.3 प्रतिशत मत एवं 63 से 62.3 प्रतिशत सीटें मिली। आंध्रप्रदेश में 41.7 से 47.3 प्रतिशत मत एवं 187 से 177 सीटें। तमिलनाडु में 1957 एवं 1962 में इसकी सरकार थी। इसमें 45.5 से 46.1 प्रतिशत मत एवं 67.4 से 73.6 प्रतिशत सीटें मिली। महाराष्ट्र में 48.7 प्रतिशत से 51.2 प्रतिशत 1952 एवं 1962 में मिले। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि काँग्रेस पार्टी का वर्चस्व राज्यों में काफी अधिक था हालांकि इसे ज्यादा वोट नहीं प्राप्त हुए। वास्तव में इसमें सभी विधान सभाओं में बहुमत से भी अधिक सीटें जीतीं क्योंकि वहाँ विपक्ष कमजोर एवं बिखरा हुआ था।

### 15.3.2 काँग्रेस पार्टी का पतन : 1967—1989

काँग्रेस पार्टी का राज्यों में वर्चस्व 1960 के मध्य में टूटना शुरू हो गया था। 1967 के आम चुनावों के बाद इसमें और बढ़ोतरी हुई। राज्यों में 1989 तक राजनीतिक दलों में इजाफा हुआ एवं ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिला इसने काँग्रेस को कमजोर किया क्योंकि ज्यादातर राज्यों में विपक्ष के रूप में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस ध्रुवीकरण का असर 1967 से 1989 तक राज्यों में दिखाई दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एवं दिल्ली में काँग्रेस एवं भारतीय जन संघ या जनता पार्टी के बीच मुकाबला था। जबकि केरल, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों एवं काँग्रेस के बीच सीधा

मुकाबला था। पंजाब, जम्मू-कश्मीर, आंध्रप्रदेश, असम एवं गोवा में क्षेत्रीय पार्टियों और काँग्रेस के बीच मुकाबला था। तमिलनाडु में यह मुकाबला डी. एम. के. एवं ए. आई. ए. डी. एम. के बीच में था। जबकि उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक, में काँग्रेस का मुकाबला नहीं दिखाई दिया। लेकिन इन राज्यों में भी बाद के वर्षों में विपक्ष-मजबूती के साथ उभर कर सामने आया। राज्यों की विधान सभा चुनावों में भी 1967 के बाद यही ध्रुवीकरण देखने को मिला। हमें यह नोट करना होगा कि काँग्रेस का मत प्रतिशत लोक सभा चुनावों की तुलना में विधान सभा में ज्यादा गिरावट दर्ज की गयी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश एवं दिल्ली में, गैर काँग्रेसी वोटों में बढ़ोतरी दर्ज की गयी। विशेषकर भारतीय जन संघ या भारतीय जनता के वोटों में। बाद में यह पार्टी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी उभर कर सामने आयी थी। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, असम, गोवा में क्षेत्रीय पार्टियों उभर कर सामने आयी। हालांकि ये दलें अस्थिर थीं।

हम इन बदलावों का आकलन करेंगे कि किस तरह के बदलाव आये। हम राज्य विधान सभा चुनावों में दलीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं काँग्रेस पार्टी को 50 प्रतिशत से अधिक संसदीय या विधान सभा चुनावों में मत हासिल नहीं हुए थे। कुछ राज्यों में इसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। यह इसलिए हुआ क्योंकि इन राज्यों में विपक्ष बिखरा हुआ था और वोटिंग पैटर्न विशेष होने के कारण काँग्रेस को इसका फायदा मिला। 1967 में विपक्ष एकजुट हुआ। इसका परिणाम यह निकला कि ज्यादातर राज्यों में गैर-काँग्रेस गठबंधन उभर कर सामने आया जिसने विधान सभाओं के चुनावों में काफी प्रभावी प्रदर्शन किया। इस गठबंधन ने काँग्रेस को आठ राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। इसी दौरान हुए संसदीय चुनावों में काँग्रेस का मत प्रतिशत 44.72 प्रतिशत से घटकर 40.7 प्रतिशत रह गया। विधान सभाओं में यह घटकर 43.65 प्रतिशत से 39.96 प्रतिशत रह गया। इसके परिणामस्वरूप सीटों की संख्या में भी गिरावट हुई 61.3 प्रतिशत से घटकर 48.5 प्रतिशत रह गयी। भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण की शुरुआत हो गयी जिसमें मुख्य मुकाबला, काँग्रेस एवं संयुक्त विपक्षी दलों के बीच में था। यह सिलसिला 1980 के अंत तक चला, हालांकि 1971 एवं 1972 में काँग्रेस अपनी स्थिती मजबूत करने में सक्षम रही। हमें यह भी देखना होगा कि काँग्रेस ने 1972 में कुछ समय के लिए वापसी की थी। यह स्थिति 1970 के अंत कम होती चली गयी।

हम यहाँ संक्षिप्त रूप में 1970 के दौरान हुए परिवर्तन पर नजर डालेंगे। उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में 1974 के विधान सभा चुनावों से लेकर 1985 के संसदीय चुनावों तक काँग्रेस पार्टी को 40 प्रतिशत से अधिक मत नहीं मिले। हालांकि 1984 में काँग्रेस की जबरदस्त जीत हुई थी। भारतीय जन संघ या जनता पार्टी ने तथा लोक दल के घटकों ने काँग्रेस पार्टी को जबरदस्त टक्कर दी। भारतीय जनसंघ ने 1974 में, 17.1 प्रतिशत मत प्राप्त किये तथा विधान सभा में 61 सीटें जीती। 1977 में, आपातकाल के पश्चात काँग्रेस पार्टी का जनता पार्टी ने सफाया कर दिया। इसके बाद 1980 में काँग्रेस वापस सत्ता में लौटी। लेकिन इसे 37.7 प्रतिशत मत ही प्राप्त हुए। 1985 में काँग्रेस को 39.3 प्रतिशत मत मिले। हालांकि इसने बहुमत प्राप्त किया। लोकदल को 21.3 प्रतिशत मत एवं 84 सीटें प्राप्त हुईं। महाराष्ट्र में काँग्रेस पार्टी को 1978 एवं 1980 में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1978 के चुनावों में काँग्रेस पार्टी का सफाया हुआ, 1985 में हालांकि काँग्रेस को बहुमत मिला लेकिन इसके मत प्रतिशत मात्र 24 प्रतिशत थे। गुजरात में भी 1960 के दशक में द्विदलीय व्यवस्था की स्थापना हुई। काँग्रेस पार्टी को एन.सी.ओ (इंडियन नेशनल काँग्रेस, आर्गनाइजेशन का सामना करना पड़ा तथा 1985 में जनता पार्टी प्रमुख दल के रूप में उभरी। 1970 में हुए चुनावों में एन.सी.ओ. को 23 प्रतिशत वोट मिले, हालांकि इसकी सीटों की संख्या काफी नहीं थी। जनता पार्टी को 20 प्रतिशत मत एवं 14 सीटें ही प्राप्त हुई थी।

मध्यप्रदेश में काँग्रेस पार्टी का मुख्य मुकाबला 1972, 1980, 1985 में भारतीय जनसंघ एवं भारतीय जनता पार्टी से था। इसे 1977 जनता पार्टी का सामना करना पड़ा। 1980 में भारतीय जन संघ को 28.7 प्रतिशत मत एवं बी.जे.पी. को 30.3 प्रतिशत मत मिले, तथा 1985 में काँग्रेस को मात्र 32.4 प्रतिशत मत ही मिले। 1977 में जनता पार्टी को 47.3 प्रतिशत मत प्राप्त हुए तथा इसने राज्य में सरकार बनाई। बिहार में, 1972 से 1985 के बीच काँग्रेस पार्टी को 35 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं हुए। इसे भारतीय जन संघ, बी.जे.पी., एन.सी.ओ., जे.एम.पी. एवं लोकदल का सामना करना पड़ा। दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु में, 1967 से लेकर आज तक दो प्रमुख दलों के बीच ही मुकाबला रहा है। पहले काँग्रेस एवं डी. एम. के. के बीच तथा अब डी.एम.के. एवं ए. आई ए.डी. एम. के. के बीच आंध्र प्रदेश में काँग्रेस पार्टी का जनाघाट 1978 से ही गिरने लगा। 1983 से प्रदेश में दो पार्टियों के बीच मुकाबला होने लगा। पश्चिम बंगाल में काँग्रेस का वर्चस्व 1967 से ही समाप्त होने लगा तथा 1971 में द्विदलीय मुकाबला होने लगा। इस प्रकार, पूरे देश में, छोटे राज्यों को छोड़कर, काँग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हुई एवं दो दलों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। इन सब कारणों के पीछे काँग्रेस का टूटना ही प्रमुख कारण था।

#### अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) चुनाव आयोग द्वारा वर्गीकृत विभिन्न राजनीतिक दलों को परिभाषित कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

2) काँग्रेस वर्चस्व (प्रभुत्व) के गुण का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए।

.....

.....

.....

.....

.....

### 15.4 राज्य दलीय व्यवस्था में बिखराव : 1989 से

1980 से लेकर 1990 के बीच राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर दलीय व्यवस्था में बिखराव देखने को मिला है। इन बिखराव के कारणों का क्या लक्षण है? राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी वर्चस्व समाप्त हुआ तथा बहु दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो व्यवस्था राज्यों में है वह राष्ट्रीय स्तर पर अलग है। कई राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था स्थापित हुई और यह लक्ष्य ही खासतौर पर राज्यों में देखने को मिला है।

राष्ट्रीय स्तर पर 1990 के दशक से मुख्य मुकाबला दो प्रमुख गठबंधनों के बीच सिकुड़ कर रह गया है। एक जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है तथा दूसरा जिसका नेतृत्व

काँग्रेस पार्टी करती हैं। राज्य स्तर पर प्रतिद्वंदी दल हर राज्य में अलग-अलग हैं, लेकिन ज्यादातर राज्यों में दो दलीय व्यवस्था ही है। कई राज्यों में बहु-दलीय व्यवस्था भी है जहाँ मुख्य मुकाबला काँग्रेस, बी.जे.पी एवं क्षेत्रीय दलों के बीच होता है। कुछ राज्यों में मुकाबला क्षेत्रीय दलों के बीच ही होता है। हालाँकि इन राज्यों में भी राष्ट्रीय दल महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम उन कारणों का पता लगायेंगे जहाँ राज्यों में इस प्रकार की व्यवस्था को उभरने दिया। वैसे तो इसके कई कारण हैं लेकिन मुख्य कारण, काँग्रेस का पतन एवं बी.जे.पी. के विकास का इन हिन्दी भाषी राज्यों में एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसके साथ ही साथ कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उभार भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये सारी प्रवृत्तियों 1990 से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। हम यहाँ बहुत संक्षिप्त में इन घटनाओं को देखेंगे तथा राज्यों में 1989 के बाद आये दलीय व्यवस्था में परिवर्तन के लक्षणों के बारे में समझेंगे। वैसे तो काँग्रेस पार्टी का पतन 1960 के दशक से ही शुरू हो गया था, लेकिन 1980 के अंत में यह पतन और तेजी से हुआ। हमने देखा कि काँग्रेस ने करीब दो दशकों तक राज्यों में शासन किया लेकिन धीरे-धीरे नेहरू की मृत्यु के पश्चात् इसका पतन होना शुरू हुआ। यह पतन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और अधिक तेजी से होने लगा। इसके कई उदाहरण हैं। जोया हसन ने यह दलीय दल की, काँग्रेस के पतन के जटिल कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण था राजनीतिक आधार अपने गठबंधन या पार्टी को बनाये रखने या बरकरार रखने का। वह सही है कि पार्टी का चुनावों में मतदाताओं को एकजुट करने में कमी रही थी विशेषकर 1980 एवं 1990 के दौरान। इस तरह काँग्रेस ने 1980 के अंत में राज्यों में ताकत कमजोर होने लगी। बीसवीं सदी के अंत में काँग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत एवं सीटें दोनों घटने लगी लोकसभा एवं विधान सभा चुनावों में। काँग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कई राज्यों में बहुत निराशा जनक रहा। इसके कई उदाहरण इस प्रकार हैं।

उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा राज्य है, काँग्रेस की ताकत इस राज्य में लगातार कमजोर हो रही है। इसका मत प्रतिशत 1993 में 15.08 प्रतिशत था जो कि गिरकर 2002 में 8.96 प्रतिशत ही रह गया था। आंध्र प्रदेश में, 1989 के चुनावों में काँग्रेस वापस सत्ता में आयी, लेकिन 1994 में इसने सत्ता गंवाई एवं 2004 तक यह विपक्ष में ही रही। बिहार में भी काँग्रेस का मत प्रतिशत 1990 में 24.78 प्रतिशत था जो कि 2000 में घटकर मात्र 11.06 प्रतिशत ही रह गया था, सीटें भी 71 से घटकर मात्र 23 ही रह गई थी। इसी प्रकार महाराष्ट्र में, 1990 में इसका प्रभुत्व पूरी तरह से खत्म हो गया था। 1990 में इसे 38.17 प्रतिशत मत मिले एवं 141 सीटें मिली लेकिन 1999 में यह घटकर 27.20 प्रतिशत मत एवं 75 सीटें रह गयी। तमिलनाडु में काँग्रेस पार्टी पूरी तरह से क्षेत्रीय पार्टियों से मात खा गयी। यहाँ डी.एम.के. एवं ए.आई.ए.डी.एम.के दो प्रमुख दलों के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा है। पश्चिम बंगाल में भी काँग्रेस का पतन 1990 के दशक से शुरू हो गया था। क्योंकि बंगाल में काँग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था और एक नई पार्टी बनी तृणमूल काँग्रेस। 2001 के चुनावों में काँग्रेस को यहाँ मात्र 7.98 प्रतिशत मत मले एवं 26 सीटें मिले जबकि 1996 में इसे 39.45 प्रतिशत मत एवं 82 सीटें मिली थी।

भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हाल के वर्षों में, ज्यादा देखने को मिला है बजाय काँग्रेस के पतन के। यह विस्तार काँग्रेस के पतन के कारण ही हुआ है तथा बी.जे.पी ने कुछ ऐसी रणनीति अपनाई एवं हिन्दुत्व जैसे मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाया जिससे इसे अधिक फायदा मिला। लोक सभा चुनावों में जहाँ बी.जे.पी. को मात्र 2 सीटें मिली। 1984 में वही 1998 में यह बढ़कर 182 हो गयी थी। इसी कारण यह पार्टी एक शासक पार्टी बनकर गयी है। 1999 के चुनावों में भी बी.जे.पी. को उतनी ही सीटें मिली फिर भी इसने गठबंधन करके सत्ता हासिल की। लेकिन इसके बाद 2004 के चुनावों में बी.जे.पी. का प्रदर्शन कमजोर



रहा। विधान सभा चुनावों में भी बी.जे.पी. का प्रदर्शन शानदार रहा है परन्तु 2014 और 2019 के लोक सभा चुनावों में फिर इसने अपने प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसके मत प्रतिशत एवं सीटें दोनों ही प्रमुख राज्यों में बढ़ी। बिहार में 1970 में इसका मत प्रतिशत 11.61 एवं 39 सीटें था वहीं यह बढ़कर 2000 में 14.64 प्रतिशत मत एवं 67 सीटें हो गया।

उत्तर प्रदेश में, भी इसकी सीटों की संख्या में इजाफा हुआ, लेकिन 2002 में यह घट गया। गुजरात में इसके मत प्रतिशत 1990 में 26.69 प्रतिशत थे जो 1998 में 44.81 प्रतिशत हो गये एवं 2002 में 49.85 प्रतिशत हो गये। यह वृद्धि कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिली। कुछ राज्यों में इसने अकेले ही सरकार बनाई जैसे मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जबकि कुछ राज्यों में गठबन्धन करके सरकार बनाई जैसे 1995 में महाराष्ट्र में शिव सेना के साथ। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस दौरान यह देखने को मिला कि राज्यों में क्षेत्रीय दलों का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ। इन राज्यों में भी काँग्रेस के कमजोर होने का फायदा इन दलों को मिला एवं इन दलों ने 1996 के चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन क्षेत्रीय दलों ने 1991 के लोक सभा चुनावों में 56 सीटें जीती, 1996 में 137, 1998 में 161 तथा 1999 में 188 सीटें जीती थी। राज्यों में भी इनकी संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। इन दलों ने राज्यों में न केवल अपनी सीटें बढ़ाई बल्कि कई राज्यों में सरकार भी बनाई। शिव सेना से पहली बार 1995 में बी.जे.पी. के साथ मिलकर सरकार बनाई। असम गण परिषद ने भी 1996 में सरकार बनाई, नेशनल काँग्रेस ने 1996 में जम्मू एवं कश्मीर में सरकार बनाई। 1990 के पश्चात तमिलनाडु में दो ही प्रमुख दलों की सरकार बनी। आंध्रप्रदेश में टी.डी.पी 1995 में सत्ता में आई और 2004 तक सत्ता में बनी रही। अकाली दल ने भी 1997 में पंजाब में सरकार बनाई। इस प्रकार के दल 1990 से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बहुत सफल रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1989 के पश्चात् भारतीय दलीय व्यवस्था में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। काँग्रेस के प्रभुत्व के काल के बाद एक बंटा हुआ युग या बिखराव वाला युग कह सकते हैं। इस काल में मुख्य मुकाबला दो ही दलों के बीच रहा है। चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो या राज्य स्तर पर। इस दौरान जो प्रतिस्पर्धा रही दलों के बीच इसे हम चार भागों में बाँट सकते हैं। पहली श्रेणी में वे राज्य है जहाँ दो ही दलों के बीच मुकाबला रहा है, वे राज्य है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात। इस श्रेणी में महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, त्रिपुरा एवं पंजाब भी आये हैं। दूसरी श्रेणी में वे राज्य है जहाँ तीन या तीन से ज्यादा दल है। जैसे कि बिहार, कर्नाटक, एवं उड़ीसा इत्यादि। तीसरी श्रेणी में वे राज्य हैं जहाँ चार दलों के बीच मुकाबला है। जैसे कि उत्तर प्रदेश। यहाँ, बी.जे.पी., काँग्रेसी, समाजवादी पार्टी एवं बी.एस.पी. के बीच मुख्य मुकाबला रहा है। चौथी श्रेणी में वे राज्य हैं जहाँ मुख्य मुकाबला दो ही दलों के बीच में है लेकिन तीसरी पार्टी का भी विकास हो रहा है। इस पार्टी का मत प्रतिशत बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

## अभ्यास प्रश्न 2

टिप्पणी: क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) भारत में बहु-दलीय व्यवस्था के विकास की व्याख्या कीजिए।

.....

.....

.....

.....

## 15.5 सारांश

इस इकाई में हमने राजनीतिक दलों के विकास का विश्लेषण किया है। विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुए परिवर्तन का परीक्षण किया है। हमारी चर्चा मुख्य रूप से राज्य दलीय व्यवस्था के लक्षणों तक ही सीमित रही हैं। हमने क्षेत्रीय दलों के बारे में चर्चा की है जो कि हाल के वर्षों में उभर कर सामने आये हैं तथा भारतीय राज्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमने यह भी देखा कि किस तरह से काँग्रेस जो कि पिछले दो दशकों से केन्द्र एवं राज्यों में मजबूत भी उसका पतन हुआ। दलीय व्यवस्था में परिवर्तन एक दलीय व्यवस्था से बहु-दलीय व्यवस्था में तबदील हुआ है। इसने काँग्रेस को और कमजोर किया तथा बी.जे.पी. के विस्तार को बढ़ावा मिला। ये बदलाव 1967 से ही शुरू हो गये थे लेकिन इनमें 1990 के पश्चात् और तेजी से वृद्धि हुई। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बड़ी तेजी से बदलाव आये हैं। काँग्रेस पार्टी के कमजोर होने के कारण भारतीय दलीय व्यवस्था में बिखराव उत्पन्न हुआ। इस व्यवस्था में मुख्य मुकाबला दो ही दलों या घटकों के बीच था। इससे यह साबित होता है कि यह व्यवस्था अभी और रहेगी तथा यह भी संभावना है कि और अधिक राज्य अब द्विदलीय व्यवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे।

## 15.6 संदर्भ सूची

वीनर, मायरॉन, (1972) *पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया : द डेवेलपमेंट ऑफ ए मल्टी-पार्टी सिस्टम*, लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस।

हसन, जोया, (2006), *पार्टीस एंड पार्टी सिस्टम*, नई-दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

## 15.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

- 1) चुनाव आयोग के अनुसार, राजनीतिक दलों को तीन भागों में बाँटा गया है। राष्ट्रीय दल, राज्य दल एवं पंजीकृत दल। राष्ट्रीय पार्टी वह है जिसकी चार राज्यों में पहचान हो। राज्य दल का क्षेत्रीय दल वह है जिसमें किसी राज्य में विगत पाँच वर्षों में राज्य की राजनीति में सक्रिय रही हो तथा जिसने चार प्रतिशत सीटें आम चुनाव में तथा तीन प्रतिशत सीटें राज्य चुनाव में जीती हो। पंजीकृत पार्टी वह है जो कि केवल चुनाव आयोग में ही पंजीकृत हो। इसे ना राज्य दल ना ही राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं मिली है।
- 2) काँग्रेस पार्टी का वर्चस्व 1967 तक अर्थात् चौथे आम चुनाव तक देखा जा सकता है। 1967 से पहले काँग्रेस पार्टी का ही वर्चस्व था सिवाय जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर जहाँ नेशनल काँग्रेस एक मजबूत ताकत बनकर उभरी तथा केरल में सी.पी.आई. विजयी बनकर उभरी।

अभ्यास प्रश्न 2

- 1) 1980 से लेकर 1990 तक दलीय व्यवस्था में काफी विखंडन देखने को मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर बहु-दलीय व्यवस्था का विकास एवं राज्य स्तर पर दो दलीय व्यवस्था का विकास देखने को मिला। बहु-दलीय व्यवस्था के उभरने का प्रमुख कारण था काँग्रेस पार्टी का पतन एवं क्षेत्रीय दलों का उभार राज्यों में। काँग्रेस पार्टी के पतन के कारण हिन्दी भाषी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का विकास बहुत तेज गति के साथ हुआ।

## संदर्भ सूची

ऑस्टीन, ग्रेनविल (1964), *कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया*, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

ई.पी.डब्ल्यू (2017), "स्पेशल इश्यूज ऑफ लाइफ एंड आइडिया ऑफ लोहिया", खंड 45, नं. 40, 2-8 अक्टूबर.

उपाध्याय, कैरोल (2016), *रिजंजरिनयरिंग इंडिया : वर्क, कौंटिल, क्लास इन एन ऑफ शोर इकॉनमी*, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

कपिल कुमार, (1984), *पीसेंटस इन रिवोल्ट : टेनेंटस, लैंडलॉर्डस, काँग्रेस एंड राज इन औध*, 1986-1992, नई दिल्ली.

कोठारी, रजनी, (1970), *कास्ट इन इंडिया*, हैदराबाद, ब्लैकस्वान.

कोठारी, रजनी, (1975), *डेमोक्रेटिक पॉलिटि एंड सोशल चेंज इन इंडिया : क्राइसिस एंड ऑपरच्यूनितिस*, बंबई, अलाइड प्रकाशन.

कोठारी, रजनी, (1989), *पोलिटिक्स एंड दि पीपल : इन सर्च ऑफ ह्यूमेन इंडिया*, दिल्ली, अजन्ता प्रकाशन, खंड, I-II.

कोठारी, रजनी (1973), *पॉलिटिक्स इन इंडिया*, ओरियंट ब्लैक स्वान।

कश्यप, सुभाष, (1955), *हिस्टरी ऑफ द पार्लिमेंट ऑफ इंडिया*, खंड-2, नई दिल्ली, शिप्रा प्रकाशन।

खोसला, माधव (2012), *द इंडियन कंस्टीट्यूशन*, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

गुप्ता, दीपाकर, (2000), *इन्टेरोगेटिंग कास्ट : अंडरस्टैंडिंग हाइरारकी एंड डिफरेंस इन इंडियन सोसाइटी*, पेंगविन.

गुहा, रंजीत, (1983), *एलिमेंट्री अस्पेक्टस ऑफ पीसेंट इनसर्जनसी इन कॉलोनियल इंडिया* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.

ग्रेनविल ऑस्टिन (2012), *दि इंडियन कंस्टीट्यूशन : कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन*, नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

गैल ओम्बेट, (1993), *रिइनेवांटिंग रेवल्यूशन : न्यू सोशल मूवमेंटस एंड सोशलिस्ट ट्रेडिशन इन इंडिया*, एम. ई. साप्रे, आरमोंक.

चागला, एम.सी.जी.बी. मुखर्जी, (1977), *कंस्टीट्यूशनल एमेंडमेंटस-ए स्टडी*, कलकत्ता, रूपक प्रकाशन.

चंडोक, नीरा (1995), *स्टेट एंड सिविल सोसाइटी इन पोलिटिकल थ्योरी*, नई-दिल्ली, सेज प्रकाशन।

चंडोक, नीरा, (1999), *बीयोंड सेक्यूलरिज्म : द राइटस एंड रिलिजियस माइनोरिटिस*, नई-दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.

- चौबे, सिवानी (2009), *द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कंस्टीट्यूशन*, नई दिल्ली, एन. बी.टी.।
- चौबे, सिवानी किंकर (2009), *स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कंस्टीट्यूशन*, नई दिल्ली, एन. बी. टी.
- चंद्र, बिपिन, (1988), मुखर्जी, मृदुला, मुखर्जी, आदित्य, महाजन, सुचित्रा, एवं पाणिकर, के. एन. (1988) *इंडिया'स स्ट्रगल फॉर इंडेपेंडेंस*, नई दिल्ली, पेंगविन.
- छिब्रर, विवेक, (2004), *लॉकड इन प्लेस : स्टेट बिल्डिंग एंड लेट इंडस्ट्रीयलाइजेशन* तुलिका प्रकाशन, दिल्ली.
- जैनिंग, सर—आइवर— (1969), *कैबिनेट गर्वनेमेंट*, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस.
- जैफरलो, फ्रिस्टोफ एएन कुमार, संजय (संकलित), *राइज ऑफ प्लेबियन? चेंजिंग फेस ऑफ द इंडियन लेगिस्लेटिव असंब्ली*, नई दिल्ली, राउटलेज।
- दास, बी.सी. (1977), *प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया*, आर. आर. नई—दिल्ली, प्रिंटर।
- दामोदरन, हरीश, (2008), *इंडिया'स न्यू कौपिटलिस्टस : कास्ट, बिजनेस, एंड इंडस्ट्री इन ए मॉडर्न इंडिया*, रिशिकेश, परमानेंट ब्लैक.
- नारायण, इकबाल (1976), *पोलिटिक्स ऑफ स्टेट इन इंडिया*, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ।
- पटनायक, उत्सा, (1987), *पीसैंट क्लास डिफरेंसिएशन : एक स्टडी इन मेथड वीद रेफरेंस टू हरियाणा*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- पटनायक, रघुनाथ — (1969), *पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गर्वनर ऑफ इंडिया*, नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप।
- पाई, सुधा, (2010), *डेवलपमेंटल स्टेट एंड द दलित क्योशचन इन मध्य प्रदेश कांग्रेस रेस्पॉंस*, नई—दिल्ली, राउटसेज, 2010.
- पारेख, भीखू (1989) *कॉलोनियलिज्म, ट्रांजिशन एंड रिफॉर्म : एन एनाल्यसिस ऑफ गाँधी'स पॉलिटिकल डिस्कॉर्स*, नई—दिल्ली.
- पारेख, भीखू (2006), *रिथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म*, न्यूयार्क, पालग्रेव, मैकमिलान।
- पाणिकर, के. एन (1990), *इंट्रोडक्शन द, सोशल साइंटिस्ट*, खंड, 18, नवंबर, 8.9, अगस्त—सितम्बर 1990.
- पी. एम. बक्शी (1999), *दि कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया*.
- बटव्याल, राकेश, (2005) *कम्यूनलिज्म इन बंगाल, फ्रॉम फेमिन टू नौखाली, 1943—47*, सेज प्रकाशन, नई—दिल्ली.
- ब्रीमन, जन, (1966), *फूटलूज लेबर वर्किंग इन इंडिया'स इनफोर्मल इकॉनमी*, कैम्ब्रीज, कैम्ब्रीज यूनिवर्सिटी प्रेस.
- ब्रास टॉम, (2000), *पीसैंट्स पोप्युलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म फ्रैक कास लंदन*.
- बसु, दुर्गा दास (2004), *इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया*, वधवा, नागपुर.
- बसु, दुर्गादास, (1983), *कमेंटरी ऑन दी कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया*, नई दिल्ली, प्रेंटीस हाल।
- बसु—डी. डी (2011), *इंट्रोडक्शन टू द कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया*, लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ वार्धा।

- बर्क, बर्बरा, (1992), *क्लास, स्टेट एंड डेवेलपमेंट इन इंडिया*, सेज प्रकाशन नई दिल्ली।
- बर्धन, प्रणब, (1998), *पोलिटिकल इकानोमी ऑफ डवलपमेंट इन इंडिया*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
- बिलग्रामी, अकिल, (2012), *सेक्यूलरिज्म : इट्स कान्टेंट एंड कान्टेक्सट*, ई.पी.डब्ल्यू. न. 4, खंड 57,
- भांभरी, सी. पी. (1989), *दि इंडियन स्टेट : कंफ्लिक्ट एंड कंट्राडिक्शन*, जोया हसन, एस. एन. झा एवं रशीद्दीन खान (संकलित) *द स्टेट, पालिटिकल प्रोसेस एंड आइडेंटिटी: रेफ्लेक्शन ऑन मॉडर्न इंडिया*, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली.
- भांभरी, सी. पी. (1974), *फंक्शनलिज्म इन पोलिटिक्स साइंस*, अप्रैल-जून - 1978, पेज 185-191।
- भांभरी, सी. पी. (1990), "स्टेट एंड कम्यूनलिज्म इन इंडिया", *सोशल साइंटिस्ट*, खंड, 18, नवंबर, 8-9, अगस्त-सितंबर, 1990, पेज 22-26.
- भार्गव, राजीव (संकलित), (1999), *सेक्यूलरिज्म एंड इट्स क्रिटिक्स*, नई-दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- महाजन, गुरप्रीत (2002), *द मल्टिकल्चरल पात: इश्यूस ऑफ डारवरसिटी एंड डिसक्रीमिनेशन इन डेमोक्रेसी*, नई-दिल्ली, सेज प्रकाशन।
- महाजन, गुरप्रीत (1998), *डेमोक्रेसी, डेसेंट एंड सोशल जस्टिस*, ऑक्सफोर्ड, लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- रमागुन्डम, राहुल, (2008), *गाँधी'स खादी : ए हिस्टरी ऑफ कॉन्टेशन एंड कॉक्सलिएशन*, हैदराबाद, ओरियंट लॉंगमैन.
- रुडोल्फ एवं रुडोल्फ, (2008), *एक्सप्लेनिंग इंडियन डेमोक्रेसी : ए फिफ्टी-ईयर परस्पेक्टिव*, *द रेलम ऑफ आइडियास इन्क्यारी एंड थ्यारी*, खंड 1.
- रुडोल्फ एवं रुडोल्फ, (2006), *पोस्टमॉडर्न गाँधी एंड अदर ऐसेस*, नई-दिल्ली, ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस.
- रुडोल्फ एण्ड रुडोल्फ, (1967), *मोडरनिटी ऑफ ट्रेडिसन: पॉलिटिकल डेवेलपमेंट इन इंडिया*, ओरियंट लांगमैन.
- रुडोल्फ एण्ड रुडोल्फ, (1987), *पोलिटिकल इकॉनमी ऑफ इंडियन स्टेट*, ओरियंट लॉंग मेन, हैदराबाद.
- वनायक, अचिन, (2017), "हिन्दूत्वा राइजिंग : सेक्यूलर क्लेमस, क्यूमनल रीयालटीस", नई-दिल्ली, तूलिका
- वीनर, मायरॉन, (1972) "पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया" : *द डेवेलपमेंट ऑफ ए मल्टी-पार्टी सिस्टम*, लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस।
- शाह, घनस्याम, (1974), *दि अपराइजिंग इन गुजरात*, ई.पी.डब्ल्यू. अगस्त 9.
- शाह, घनस्याम, (2001), *सोशल मूवमेंट्स एंड द स्टेट* नई दिल्ली, सेज प्रकाशन.
- शाह, घनस्याम (सं.) (1990), *सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया*, सेज प्रकाशन नई दिल्ली।
- सरकार, सुमित (1983), *मार्डन इंडिया, 1885-1947*, नई दिल्ली, मैक्मिलन.

सिंह, जगपाल (1992), *कैपिटलिज्म एंड डिपेंडेंस : अग्ररेरियन पोलिटिक्स इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश*, (1957-1991), मनोहर, नई दिल्ली.

सिंह, के. एस. (1982, 1983), (संकलित) *ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया*, खंड I & II, मनोहर.

हसन, जोया (2000), *स्टेट एंड पोलिटिकल इन इंडिया*, नई-दिल्ली सेज प्रकाशन।

हसन, जोया (1990), *चेंजिंग ओरियंटेशन ऑफ द स्टेट एण्ड एमर्जेस ऑफ मेजोरिटेरिनिज्म इन द 1980* सोशल साइंटिस्ट, अगस्त-सितम्बर।

हसन, जोया, (2006), *पार्टीस एंड पार्टी सिस्टम*, नई-दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

हरारी, युवाल नोह, (2018), *21 लेशन्स फॉर द 21 स्ट सेंचूरी*, लंदन, जोनाथन कैप।



MPDD/IGNOU/P.O. 94.5K/December, 2019



ISBN : 978-93-89668-66-7